भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 55

बुधवार, 07 दिसम्बर, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए

पीएम गतिशक्ति – एनएमपी

55. श्री सुब्रत पाठक:
श्री विद्युत बरन महतो:
श्री रवि किशन:
श्री रविन्दर कुशवाहा:
श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे:
श्री प्रतापराव जाधव:
श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक:
श्री सुधीर गुप्ता:
श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में मल्टी-मोडल कनेक्टिविटी के लिए पीएम गति शक्ति – नेशनल मास्टर प्लान (एनएमपी) के उद्देश्य और विशेषताएं क्या है;
(ख) प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;
(ग) योजना के तहत विभिन्न विभागों/मंत्रालयों द्वारा चिन्हित की गई प्रमुख परियोजनाओं का ब्यौरा और उनकी संख्या कितनी है तथा इसकी अनुमानित लागत कितनी है;
(घ) योजना के प्रारंभ से अब तक इसके लिए आबंटित और जारी की गई निधियों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;
(ड.) महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और झारखंड राज्य में शुरू की गई परियोजनाएं कौन-कौन सी हैं तथा इसमें कितनी राशि अंतर्ग्रस्त है; और
(च) समयबद्ध तरीके से बुनियादी ढांचे की निर्बाध आयोजना और परियोजनाओं के समन्वित निष्पादन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सोम प्रकाश)

(क), (ख) और (च): पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (एनएमपी) एक जीआईएस आधारित प्लेटफार्म है, जिसमें सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के पोर्टल है जिसकी शुरूआत अक्टूबर, 2021 में हुई थी जिसका उद्देश्य एकीकृत योजना हेतु डेटा आधारित निर्णय लेना, परियोजनाओं को प्राथमिकता प्रदान करना, कार्यान्वयन में ताल-मेल बैठाना, लागत और समय को कम करना तथा परियोजना की निगरानी करना है जिससे पूरे देश में मंत्रालयों/विभागों द्वारा विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों को मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी अवसंरचना के विकास को सुविधाजनक बनाना ताकि इससे आर्थिक क्लस्टरों को अंतिम छोर तक की कनेक्टिविटी को सुविधाजनक बनाया जा सके और इससे लॉजिस्टिक्स लागत को कम किया जा सके। बेहतर निर्णय लेने और विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के बीच समन्वय सुनिश्चित करने के लिए, संस्थागत व्यवस्था के रूप में सचिवों का अधिकार-प्राप्त समूह (ईजीओएस) और नेटवर्क योजना समूह (एनपीजी) बनाया गया है। एनएमपी पर अब तक विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों/राज्य सरकारों के लगभग 2000 डाटा लेयर अपलोड किए गए हैं। नीति आयोग के अलावा, पीएम गति शक्ति के भाग के रूप में 24 केंद्रीय मंत्रालय/विभाग हैं, जो अपने सचिवों के माध्यम से ईजीओएस में प्रतिनिधित्व करते हैं। विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी करने और ईजीओएस द्वारा परियोजनाओं की जांच करने और सिफारिश करने के लिए नियमित अंतराल पर एनपीजी की बैठकें आयोजित की जाती हैं।

(ग) और (ङ): महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और झारखंड राज्य से गुजरने वाली परियोजनाओं सहित, पीएम गति शक्ति के तहत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा चिन्हित परियोजनाओं की सूची निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध कराई गई हैं।

https://dpiit.gov.in/sites/default/files/Parliament_Questions_Logistics_Division.pdf

(घ) : पीएम गति शक्ति मल्टीमॉडल अवसंरचना की एकीकृत योजना से संबंधित डेटा आधारित निर्णयों को सुविधाजनक बनाने के लिए एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण है।
अवसंरचना विकास के लिए राज्यों द्वारा बढ़े हुए पूंजीगत व्यय के लिए, वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने "2022-23 हेतु पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना" के माध्यम से शून्य ब्याज दर पर दीर्घकालिक ऋण के रूप में राज्यों के बीच संवितरण के लिए 6 अप्रैल 2022 को 1,00,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया है। इसमें से योजना के भाग-II के तहत 5,000 करोड़ रुपये विशेष रूप से पीएम गतिशक्ति संबंधित व्यय के लिए प्रदान किए गए हैं।

*****